देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित देहरादून, बुधवार, 25 दिसंबर 2019 www.page3news.in नगर संस्करण वर्ष 14 अंक: 286 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

पेज थ्री

विचार-प्रवाह...
उपद्रवी तत्वों की साजिश

PAGE 3 PUBLICATION

मौसम अधिकतम 17.0° न्यूनतम 7.0°

41461.26 **2** यूक्रेन को अमेरिकी मदद पर रोक **7** विराट साल के आखिर में टॉप पर

संक्षिप्त समाचार

आज दो नई योजना लॉन्च करेगी केंद्र सरकार

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। केंद्र सरकार बुधवार को दो नई योजनाओं का शुभारंभ करने जा रही है। इन दोनों योजनाओं के नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल जल और अटल टनल रखा गया है। आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के बाद आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश के सात राज्यों में पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए अटल जल योजना लॉन्च की जाएगी। योजना के लिए 6 हजार करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है।

सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे हेमंत सोरेन, 27 को ले सकते हैं शपथ

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन मंगलवार रात 8 बजे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सोरेन इससे पहले शाम 7 बजे सभी विधायकों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। संभावना है कि राज्यपाल की अनुमति मिलने पर वह 27 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान में शपथ लेंगे।

पुलिस ने माना, उसकी गोली से हुई प्रदर्शनकारी की मौत

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) बिजनौर। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर बिजनौर पुलिस ने मंगलवार को माना कि जिले के नहटौर में एक प्रदर्शनकारी की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई। हालांकि पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। बता दें कि अभी तक डीजीपी ओपी सिंह ने कई बार दावा किया कि हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से फायरिंग नहीं हुई है। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि एक सिपाही ने जब उपद्रवी से पिस्तौल वापस लेने की कोशिश की तो उसने सिपाही पर गोली चला दी।

एनपीआर के अपडेशन को मंजूरी

■अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020 तक एनपीआर को अपडेट करने का काम किया जाएगा

देश भर के नागरिकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत देश भर के नागरिकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। हालांकि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। इसका इस्तेमाल सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए करती है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों से रू-ब-रू करवाते सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एनपीआर में कोई प्रूफ, कोई डॉक्युमेंट और बायोमीट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिक जो भी सूचना देंगे, वह सही मान ली जाएगी।

जनगणना का ही अपडेटेड वर्जन है एनपीआर

जावड़ेकर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इस बार जनगणना का कार्य अंग्रेजों के जमान से हो रहा है। भारत में अब तक 15 बार जनगणना का काम हुआ है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारत की आठ बार जनगणना करवाई थी, फिर आजादी के बाद सात जनगणना हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अब 16वीं जनगणना का काम बेहद आसान कर दिया गया है। इस बार तकनीकी की मदद ली जाएगी। एक ऐप लॉन्च होगा जिसमें नागरिक जो भी जानकारी देंगे, उन्हें बिल्कुल सही मान लिया जाएगा।

भारत में रह रहे हर व्यक्ति की गणना: जावड़ेकर ने बताया कि एनपीआर पहली बार 2010 में यूपीए सरकार में शुरू हुआ और सारे लोगों का रजिस्टर बना और उसके कार्ड मनमोहन सरकार ने वितरित किए थे। 2015 में इसका अपडेशन हुआ। चूंकि जनगणना का काम हर 10 साल में होता है, इसलिए 2020 में जनगणना का काम पूरा करना है। उन्होंने कहा, श्इससे सभी राज्यों ने स्वीकार किया है, सभी राज्यों ने नोटिफिकेशन निकाले हैं, सभी राज्यों में कर्मचारियों के प्रशिक्षण हो रहे हैं। जो भी भारत में रहता है, उसकी गणना इसमें होगी।

एनपीआर के ये फायदे: उन्होंने कहा कि एनपीआर से सरकारी योजनाओं के सही लाभार्थियों की पहचान हो पाएगी और यह भी पता चल पाएगा कि योजना का लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं? जावडेकर ने कहा, आयुष्मान, उज्ज्वला, सौभाग्य जैसी योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान होगी। सभी और सही लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचे, यह सुनिश्चित हो सकेगा।

क्या है एनपीआर ?

नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर और कुछ भी नहीं हर 10 वर्ष में होने वाली जनगणना का ही नया रूप है। इसके तहत 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए देशभर में घर-घर जाकर जनगणना की तैयारी है। देश के सामान्य निवासियों की व्यापक पहचान का डेटाबेस बनाना छत्त का मुख्य लक्ष्य है। इस डेटा में जनसांख्यिकी के साथ बायोमीट्रिक जानकारी भी होगी। इसमें व्यक्ति का नाम, पता, शिक्षा, पेशा जैसी सूचनाएं दर्ज होंगी। छत्त में दर्ज जानकारी लोगों द्वारा खुद दी गई सूचना पर आधारित होगी और यह नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा।

आईएमएफ की सरकार को सलाह मंदी दूर करने को लें तुरंत ऐक्शन

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) वॉशिंगटन। देश में आर्थिक मंदी को संभालने के लिए भारत सरकार को जल्दी ही कुछ कदम उठाने की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देश में जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भारत सरकार को यह सलाह दी है। भारत की इकॉनमी को दुनिया के ग्रोथ इंजनों में से एक करार देते हुए अंतरराष्ट्रीय संस्था ने कहा कि मौजूदा स्थिति से उबरने के लिए जल्दी ही कुछ कदम उठाने की जरूरत है। आईएमएफ ने अपनी सालाना समीक्षा में कहा कि उपभोक्ता मांग में कमी, टैक्स रेवेन्यू में गिरावट और अन्य कई कारणों से भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक ब्रेक जैसा लगा है।

बंगाल में सरकार बनाम राज्यपाल ?

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एक बार फिर छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा है। मंगलवार सुबह जब वह कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुंचे तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने उनके काफिले को रोक लिया। इस दौरान हंगामे की वजह से अफरातफरी का आलम है।

गवर्नर का विरोध कर रहे छात्रों ने उन्हें कार से उतरने ही नहीं दिया। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने किसी तरह छात्रों को हटाने की कोशिश की। बता दें कि आज ही यूनिवर्सिटी का दीक्षांत

छात्रों ने गवर्नर की कार रोकी, विरोध प्रदर्शन

समारोह प्रस्तावित था। इस बीच गवर्नर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कुलपति पर निशाना साधा है।

दीक्षांत समारोह रद्द करने पर बढ़ा विवाद: गवर्नर का विरोध कर रहे छात्रों ने हाथों में सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) और एनआरसी के विरोध में तख्तियां लिए नारेबाजी की। वे लगातार गवर्नर गो बैक (राज्यपाल वापस जाओ) के नारे लगाते दिखे। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों ने उन्हें काले झंडे भी दिखाए। इससे

पहले सोमवार को भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्रों ने दो बार धक्का-मुक्की करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए थे। इससे एक दिन पहले ही उन्होंने संभावित गड़बड़ी की आशंका के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 24 दिसंबर को होने वाले विशेष दीक्षांत समारोह को रद्द करने के फैसले को अवैध और अमान्य करार दिया था।

ममता बनर्जी पर वार-कानून व्यवस्था चरमराई

इस बीच राज्यपाल धनखड़ ने अपने साथ हुए बर्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए सीएम ममता बनर्जी पर इशारों में वार किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, श्एक चांसलर और गवर्नर के रूप में मेरे लिए यह बहुत दर्दनाक क्षण हैं। हमारे छात्र कन्वोकेशन में अपनी डिग्री पाने का इंतजार कर रहे हैं। उनके कठिन परिश्रम का फल। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सिस्टम को बंधक बना लिया। यूनिवर्सिटी और राज्य प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है।

राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा को मेरठ जिले की सीमा से लौटाया

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

मेरठ। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मेरठ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात के लिए जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को मंगलवार को पुलिस ने रोक लिया। दोनों नेता एक ही कार में सवार थे। मेरठ में एंट्री से पहले ही जिले के बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर दोनों नेताओं को रोका, जिसके बाद दोनों ने अपनी गाड़ी दिल्ली की तरफ मोड़ दी। राहुल ने कहा कि उन्हें किसी ऑर्डर की कॉपी नहीं दिखाई गई, बस लौटने के लिए कह दिया गया।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया पद बना

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्यॉरिटी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया पद बनाने को मंजूरी दे दी है। इस तरह जल्द ही देश को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया पद बनाने का ऐलान किया था। 1999 में करगिल रिव्यू कमिटी ने इस पद का सुझाव दिया था जो रक्षा से जुड़े मसलों पर सरकार का सिंगल-पॉइंट अडवाइजर होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का मकसद भारत के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ऐतिहासिक सैन्य सुधार की घोषणा करते हुए कहा था कि भारत की तीनों सेना के लिए एक प्रमुख होगा, जिसे सीडीएस कहा जाएगा। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद सीडीएस की नियुक्ति के तौर-तरीकों और उसकी जिम्मेदारियों को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।

मंजूरी

करगिल समीक्षा समिति ने की थी पद बनाने की सिफारिश

प्रोटोकॉल के मामले में भी सीडीएस सबसे ऊपर रहेगा। सीडीएस मुख्यतः रक्षा और रणनीतिक मामलों में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के एकीकृत सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेगा। 1999 के करगिल युद्ध के मद्देनजर देश की सुरक्षा प्रणाली में खामियों की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति ने रक्षा मंत्री के एकीकृत सैन्य सलाहकार के रूप में सीडीएस की नियुक्ति का सुझाव दिया था।

इसका फायदा क्या होगा?

इसका सबसे बड़ा फायदा युद्ध के समय होगा। युद्ध के समय तीनों सेनाओं के बीच प्रभावी समन्वय कायम किया जा सकेगा। इससे दुश्मनों का सक्षम तरीके से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। दरअसल सशस्त्र बलों की परिचालनगत योजना में कई बार खामियां सामने आईं। 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भारतीय वायुसेना को कोई भूमिका नहीं दी गई थी जबकि भारतीय वायुसेना तिब्बत की पठारी पर जमा हुए चीनी सैनिकों को निशाना बना सकती थी और उनके बीच तबाही मचा सकती थी।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you
What we do
Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.
Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS
Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.
Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in